



एस.के. हालदार  
अध्यक्ष  
सन्देश

जल क्षेत्र में आम जनता के साथ-साथ अधिक से अधिक हितधारक की प्रतिभागिता से प्रशासन संस्थागत व्यवस्था, नीति और कार्यक्रमों में विभिन्न सुधार हो रहे हैं। के.ज.आ. जल क्षेत्र में देश का प्रमुख संगठन है और सात दशकों से अधिक समय से जल संसाधन विकास और प्रबंधन में देश की सराहनीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे एक ऐसे संस्थान का नेतृत्व करने में उत्तरदायित्व का बोध होता है जिसकी विरासत प्रत्यक्ष रूप से डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और डॉ. ए.एन. खोसला से जुड़ी हुई है।

वर्ष 2020 के दौरान, सरकार द्वारा जल क्षेत्र में सुधार के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और पहले से चल रही गतिविधियों को भी गति दी गई। भारत सरकार द्वारा देश में सिंचाई क्षेत्र की वितरण सेवाओं में सुधार के लिए सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम हेतु सहयोग (सीआईएमपी) एक नई पहल है। इस संदर्भ में, के.ज.आ. द्वारा राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों में सीआईएमपी प्रस्तुत करने के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया। श्री यू.पी. सिंह, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग मुख्य अतिथि थे और वेबिनार में विभिन्न राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से बहुत सक्रिय भागीदारी

थी। श्री यू.पी. सिंह, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण ने दिनांक 24.12.2020 को सिंचाई, बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर विमर्श हेतु जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण की सलाहकार समिति की 147वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सलाहकार समिति द्वारा कुल 5 परियोजनाओं को स्वीकार किया गया।

के.ज.आ. के वरिष्ठ अधिकारी महत्वपूर्ण अंतर-विभागीय समितियों के माध्यम से गतिविधियों / योजनाओं की प्रगति की निगरानी करते हैं। इस माह के दौरान फरक्का बैराज परियोजना और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) के लिए तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की बैठकें, दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति (डीवीआरआरसी), घग्गर स्थायी समिति, उत्तर कोयल परियोजना के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति आदि की बैठक हुई।

के.ज.आ. आधुनिक तकनीकों को भी अपना रहा है और ड्रोन/यूएवी का उपयोग करते हुए स्थलाकृतिक सर्वेक्षण कार्य कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में इस तकनीक का उपयोग बैरिनियम जल विद्युत परियोजना हेतु सर्वेक्षण एवं अन्वेषण तथा अन्वेषणार्थ अन्य विभिन्न परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है। पारंपरिक तरीकों की तुलना में, यह विधि तेज़ और किफायती साबित हो रही है और विशेष रूप से पहाड़ी / उबड़-खाबड़ इलाकों के लिए अनुकूल है।

अध्यक्ष, के.ज.आ. के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान जलांश का यह पहला संस्करण है। मैं पाठकों और हितधारकों से निरंतर सुधार के लिए अपने सुझाव और प्रतिक्रिया देने के

लिए अनुरोध करता हूँ। इसके अलावा, जल क्षेत्र में काम करने वाले अन्य सहयोगी संगठन इस मासिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु जरूरी सामग्री / जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

मेरे पूर्ववर्ती, श्री आर.के. जैन, भारत सरकार में 35 वर्षों से अधिक समय तक अपनी सेवाएं प्रदान करने के उपरांत दिनांक 31.12.2020 को सेवानिवृत्त हो गए। संगठन जल क्षेत्र में उनकी सेवाओं और योगदान को सप्रेम याद करेगा। के.ज.आ. की ओर से, मैं उनके स्वस्थ और समृद्ध सेवानिवृत्त जीवन की कामना करता हूँ।

कोविड-19 महामारी द्वारा प्रभावित विषद वर्ष 2020 के बाद, हम बहुत आशा और सकारात्मकता के साथ वर्ष 2021 का स्वागत कर रहे हैं। मैं सभी को खुशहाल, समृद्ध और स्वस्थ नववर्ष 2021 की शुभकामनाएं देता हूँ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत



माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आईटीए केंद्र गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान का शुभ दीप प्रज्ज्वलन से उद्घाटन किया।



## विषय वस्तु

- एसआईएमपी पर राष्ट्रीय वेबिनार
- जल शक्ति मंत्रालय के रिसर्च चैयर (जल संघर्ष और अभिशासन) की प्रबंध समिति की दूसरी बैठक
- घग्गर स्थायी समिति की बैठक
- सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति की 147वीं बैठक
- बांदा जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश द्वारा किए गए जल संरक्षण कार्यों का दौरा.

- बैरिनियम एचईपी, जम्मू और कश्मीर का टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण
- डीवीआरआरसी की 143वीं बैठक
- फरक्का बैराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति की 116 वीं बैठक और फरक्का बैराज परियोजना सलाहकार समिति की 8 वीं बैठक
- तट बांध निर्माण के कारण सिल्टेशन पर बैठक
- देश में बाढ़ की स्थिति
- डीडी न्यूज : आपदा का सामना
- डिप के तहत गतिविधियां
- गिरि मध्यम सिंचाई परियोजना का निष्पादन

- मूल्यांकन अध्ययन
- 31.12.2020 तक योजना/घटकों की वित्तीय प्रगति
- जल क्षेत्र समाचार
- उत्तर कोयल परियोजना के लिए टीईसी की 29वीं बैठक
- ब्रह्मपुत्र बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति की 11वीं बैठक
- सैलिनिटी इंग्रेस मैनेजमेंट परियोजनाओं के लिए तीसरी बैठक
- इतिहास-शरवती हाइड्रो पावर प्लांट

## सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए सहयोग(एसआईएमपी) पर राष्ट्रीय वेबिनार

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से भारत सरकार द्वारा सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम हेतु सहयोग(एसआईएमपी) की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई। इसका उद्देश्य देश में सिंचाई क्षेत्र की वितरण सेवाओं में अर्थात जल उपयोग दक्षता (डब्ल्यूयूई) में सुधार करना, वृहद व मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं के तहत एक मानक आधुनिकीकरण दृष्टिकोण अपना कर किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करना है। एसआईएमपी के अंतर्गत एशियाई विकास बैंक (एडीबी) जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू आर डी), जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के साथ मिलकर एमएमआई योजनाओं के लिए उनके भविष्य के सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को तैयार करने में राज्यों का सहयोग करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करेगा।

इस संदर्भ में, सिंचाई आधुनिकीकरण में मौजूदा सिंचाई योजनाओं को उन्नत करना और आधुनिक सिंचाई प्रथाओं और उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को लागू करके नई योजनाओं को विकसित करना सम्मिलित करना है। एसआईएमपी की मुख्य गतिविधियाँ चिन्हित परियोजनाओं के लिए व्यवहारिक अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), विस्तृत डिज़ाइन और निविदा दस्तावेज़ों को तैयार करने के लिए लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यासों को लागू करके नए सिंचाई निवेश तैयार करने के साथ राज्यों का सहयोग करना है।



राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईएमपी लागू करने के लिए, 08.12.2020 को के.ज.आ द्वारा एक कार्यशाला / वेबिनार आयोजित किया गया था। श्री यू.पी. सिंह सचिव, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग मुख्य अतिथि थे। श्री एस के हालदार, सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), के.ज.आ, मंत्रालय और के.ज.आ.के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, एशियाई विकास बैंक (ADB) के अधिकारी वेबिनार में शामिल हुए। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिवों / विशेष सचिव जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से अधिक वरिष्ठ डब्ल्यूआरडी अधिकारियों के साथ वेबिनार में भाग लिया। एसआईएमपी के तहत रूपरेखा, राज्य की भूमिका पर प्रतिभागी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के साथ चर्चा की गई।

## जल शक्ति मंत्रालय के रिसर्च चेर (जल संघर्ष और अभिशासन) की प्रबंध समिति की दूसरी बैठक

जल शक्ति मंत्रालय के रिसर्च चेर की प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक 17.12.2020 को के.ज.आ के अध्यक्ष श्री आर. के. जैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रबंधन समिति चेर की गतिविधियों के समन्वय और रणनीतिक आदान प्रदान करने के लिए सलाहकार निकाय है। बैठक में श्री एस. के. हालदार, सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), सुश्री यामिनी अय्यर, अध्यक्ष और सीईओ, सीपीआर; श्री अश्विन पंड्या, महासचिव, आईसीआईडी; श्री विजय सरन, मुख्य अभियंता (आईएमओ), के.ज.आ. श्री टी.डी. शर्मा, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त(बीएम), जल शक्ति मंत्रालय, श्री रवि भूषण, निदेशक (आरएंडडी), जल शक्ति मंत्रालय, डॉ. श्रीनिवास चोकक्कुला, जल शक्ति मंत्रालय, रिसर्च चेर; डॉ.पार्थ मुखोपाध्याय, वरिष्ठ फेलो, सीपीआर और के.ज.आ. के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

## घग्गर स्थायी समिति की बैठक

घग्गर स्थायी समिति की 30वीं बैठक 18.12.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सदस्य(आरएम), के.ज.आ. की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

- राज्य सरकार के दृढ़ विचार एक सप्ताह के भीतर सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे को दिया जाए
- प्रारंभिक मॉडल अध्ययन का सत्यापन, डिटेन्शन बेसिन का स्थान, तटबंधों के संरेखण और अन्य जल-निकासी कार्यों आदि को राज्य सरकार द्वारा 2 सप्ताह के भीतर किया जाए
- प्रारंभिक मॉडल अध्ययन रिपोर्ट राजस्थान सरकार के साथ 1



बैठक के दौरान निम्न मुद्दों के बारे में चर्चा की गई:

- रिसर्च चेर को सलाह और इनपुट के लिए वार्षिक रिपोर्ट। इसमें निदेशक (आरएंडडी) द्वारा जल शक्ति मंत्रालय चेर पर तैयार किया गया एक संस्मरण भी शामिल था।
- के.ज.आ. और सीपीआर के बीच समन्वय को मजबूत करना और जल शक्ति मंत्रालय रिसर्च चेर अनुसंधान हितों पर घनिष्ठ सहयोग
- शोध कार्य का प्रकाशन और प्रसार।

दिन के भीतर साझा की जाए

- प्रस्तावित तटबंध के चरण- II का संरेखण पंजाब सरकार द्वारा सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे को दिया जाए
- सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे को सभी हितधारकों द्वारा विचारों / सुझावों को शामिल करने के बाद मॉडल अध्ययन रिपोर्ट पेश करनी चाहिए और घग्गर नदी की बाढ़ की समस्याओं का एकीकृत तरीके से समाधान करने के लिए झेलम बेसिन के लिए पहले के मॉडल अध्ययन के अनुरूप कुछ विकल्प देकर नदी के विभिन्न हिस्से के लिए विशिष्ट समाधान प्रदान करना चाहिए।

## सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर ज.सं.,न.वि.एवं गं.सं.वि. की सलाहकार समिति की 147वीं बैठक

सिंचाई, बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार के लिए ज.सं.,न.वि.एवं गं.सं.वि. की सलाहकार समिति की 147वीं बैठक 24.12.2020 को सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी।

बैठक में उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के अलावा के.ज.आ., जीएफसीसी, सीजीडब्ल्यूबी, जन जातीय कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सीईए, नीति अयोग और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सलाहकार समिति द्वारा कुल 5 परियोजनाओं को स्वीकार किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं	परियोजना का नाम	राज्य	परियोजना के प्रकार	अनुमानित लागत (करोड़ रु. एवं मूल्य स्तर)	लाभ
1.	ऊपरी भद्रा परियोजना	कर्नाटक	सिंचाई (वृहत)	16125.48 (2018-19)	क्षेत्र-225515 हेक्टेयर, जनसंख्या-7426485
2.	सुकला सिंचाई परियोजना की ईआरएम	असम	सिंचाई (वृहत)	259.73 (अक्टूबर -2020)	क्षेत्र-12150 हेक्टेयर, जनसंख्या- 141427)
3.	अग्रेंग सिंचाई परियोजना	असम	सिंचाई (मध्यम)	540.4585 (2019-20)	क्षेत्र -6800 हे. जनसंख्या- 10000
4.	बलरामपुर और सिद्धार्थनगर जिले में 0.00 किमी से 40.80 किमी भोजपुर शाहपुर बांध के बाकी कार्य	उत्तर प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	78.327 (2016)	क्षेत्र - 8587 हे. जनसंख्या-33200
5.	तहसील नाहन, जिला सिरमौर में मार्कंडेय नदी का चैनलाइजेशन	हिमाचल प्रदेश	बाढ़ नियंत्रण	105.66 (2019)	क्षेत्र -462.18 हे., जनसंख्या -17406

### बांदा जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश द्वारा किए गए जल संरक्षण कार्यों का दौरा

जल शक्ति मंत्रालय ने बांदा जिले का दौरा करने और तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, बांदा श्री हीरा लाल के मार्गदर्शन में किए गए जल संरक्षण कार्यों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जैसा कि प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2020 के लिए अपने आवेदन में उल्लेख किया है।

तदनुसार, श्री जी एल बंसल, निदेशक और श्री मयंक सुहृद, उप निदेशक, एमएंडए निदेशालय, के.ज.आ., आगरा ने जिला प्रशासन, लघु सिंचाई और जल निगम, यू.पी. के अधिकारियों के साथ 31 दिसंबर, 2020 से 1 जनवरी, 2021 के दौरान बांदा और आसपास के गांवों का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट



के.ज.आ.(मुख्यालय) को सौंपी।

### बैरिनियम एचईपी, जम्मू और कश्मीर का टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण

चिनाब डिवीजन, के.ज.आ., जम्मू, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के जिला किशतवाड़ में प्रस्तावित बैरिनियम एचईपी परियोजना के लिए सर्वेक्षण और जांच कार्यों का निष्पादन कर रहा है। चिनाब डिवीजन ड्रोन / यूएवी का उपयोग करके टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण का कार्य कर रहा है। पारंपरिक तरीकों की तुलना में, ड्रोन / यूएवी का उपयोग करने वाली यह विधि तेज और किफायती साबित हुई है। परियोजना क्षेत्र का इलाका बहुत ऊँची चोटियों और गहरे घाटियों वाला है।

परियोजना का क्षेत्र लगभग 44 वर्ग किमी है और गुलाबगढ़ (जम्मू-कश्मीर) से लेकर हिमाचल प्रदेश में लूज तक चिनाब नदी के किनारे तक फैला हुआ है। परियोजना क्षेत्र में खतरनाक चट्टानों का हिस्सा शामिल है इसमें दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क स्थित है जो हिमाचल में कीलॉग को जम्मू-कश्मीर में किशतवाड़ से जोड़ती है। के.ज.आ. ने दुष्कर क्षेत्र और -10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड



के बीच सबसे कम तापमान के साथ अत्यंत कठोर जलवायु में यह काम पूरा कर लिया है।

## डीवीआरआरसी की 143वीं बैठक

दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति की 143वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 18.12.2020 को श्री आर के सिन्हा, सदस्य (आरएम), के.ज.आ. और अध्यक्ष, डीवीआरआरसी की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय जल आयोग, दामोदर घाटी निगम, झारखंड सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान किए गए महत्वपूर्ण विचार-विमर्श और निर्णय निम्नानुसार हैं:

(i) 852 फीट से ऊपर के जलाशय में भंडारण के लिए तेनुघाट जलाशय के भूमि सर्वेक्षण और तेनुघाट जलाशय के लिए 817 फीट से 839 फीट के बीच इसके जल भंडारण का उपयोग जो तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड जलाशय में भारी गाद होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता है, के लिए झारखंड सरकार के प्रतिनिधि रणनीतिक योजना पर काम करें।

(ii) 1978 के अंतर्राज्यीय समझौते के अनुसार झारखंड सरकार द्वारा कोनार सिंचाई योजना के लिए जल उपयोग की योजना और तेनु-बोकारो लिंक नहर से तेनुघाट जलाशय से उतनी आपूर्ति डीवीसी प्रणाली को करने के लिए योजना एक महीने के भीतर प्रदान किया जाएगा।

(iii) झारखंड सरकार संशोधित बालपहाड़ी बहु-जलाशय सिमुलेशन की शुरुआत के लिए एक महीने के समय में "प्रस्तावित बालपहाड़ी जलाशय सहित दामोदर-बराकर बेसिन में जलाशयों के बहु जलाशय सिमुलेशन अध्ययन" के लिए अंतिम रूप दिए गए आंकड़ों पर टिप्पणियां भेजेंगे

(iv) दुर्गापुर बैराज के अपस्ट्रीम में जमा गाद को हटाने के मुद्दों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से के.ज.आ., पश्चिम बंगाल सरकार, डीवीसी और सीडब्ल्यूपीआरएस के संबंधित अधिकारियों के बीच हल किया जाए।

(v) मानसून 2020 के दौरान मैथन और पंचेत जलाशयों के लिए बाढ़ मोडरेशन का प्रदर्शन और इन जलाशयों में अच्छे भंडारण की समिति के सदस्यों द्वारा सराहना की गई।

(vi) नगरपालिका और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए दामोदर घाटी क्षेत्र से पानी का आवंटन विभिन्न फर्मों को किया गया है: यथा:- मेसर्स मा अम्बा स्पंज आयरन लिमिटेड, मेसर्स मार्क स्टील्स लिमिटेड, मेसर्स बीआरजीडी स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आर्यवर्त कर्णजी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एआईसी आयरन इंडस्ट्रीज प्रा. लि.

## फरक्का बैराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति की 116वीं बैठक और फरक्का बैराज परियोजना सलाहकार समिति की 8वीं बैठक

फरक्का बैराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी-एफबीपी) की 116वीं बैठक, फरक्का बैराज परियोजना की सलाहकार समिति, (एफबीपी-एसी) की 8वीं बैठक के साथ 18-19 दिसंबर 2020 के दौरान डॉ. आर के गुप्ता, सदस्य (डी एंड आर)/अध्यक्ष टीएसी-एफबीपी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

टीएसी-एफबीपी बैराज और इसके आश्रित संरचनाओं मुख्य रूप से गेट प्रतिस्थापन, मृदा कटाव रोकथाम और बैंक संरक्षण कार्य आदि से संबंधित विभिन्न तकनीकी मामलों पर फरक्का बैराज परियोजना के अधिकारियों को सलाह देता है। एफबीपी-एसी जिसमें संसद सदस्य, मालदा उत्तर, वैष्णवनगर, फरक्का और पाकुड़ की विधान सभा सदस्य सहित जन प्रतिनिधि एवं साथ ही परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हितधारकों ने बैठक में एफबीपी द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों पर चर्चा की। इस वर्ष के दौरान, टीएसी-एफबीपी और एफबीपी-एसी बैठकों से पहले, माननीय जल शक्ति मंत्री, सचिव, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि., आयुक्त (एफएम) और अन्य प्रतिनिधियों ने फरक्का बैराज परियोजना का दौरा किया।

श्री समीर कुमार शुक्ला, निदेशक, श्री नागराज वी, उप निदेशक और श्री धीरज पांडे, सहायक निदेशक, बीसीडी (ईएंडएनई) निदेशालय और श्री हरकेश कुमार, निदेशक, श्री साकेत कृष्ण, उप निदेशक और श्री आशीष सिंह, सहायक निदेशक, गेट्स (ईएंडएनई) निदेशालय, के.ज.आ. ने बैठक के बाद क्षेत्र के दौरे के



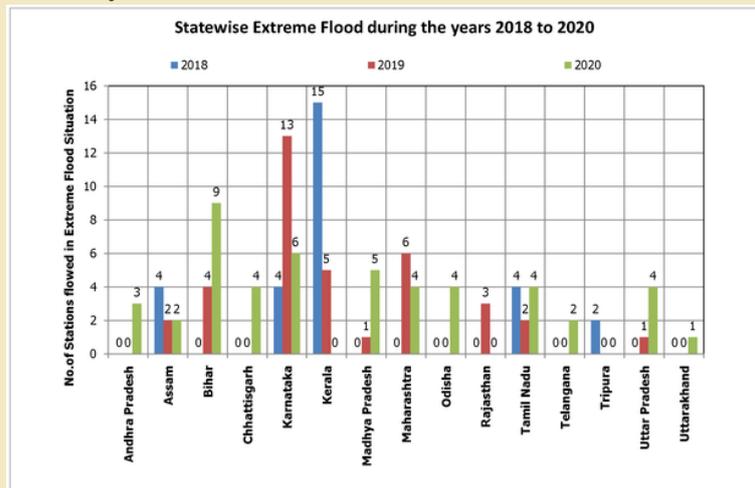
सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक



स्थानीय प्रतिनिधियों और जनता के साथ बातचीत

दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को सहायता की। बैठक से पहले 18-19 दिसंबर, 2020 के दौरान बैराज और आश्रित संरचनाओं की साइट विजिट, एफबीपी के अधिकार क्षेत्र के तहत बैराज और फीडर नहर के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में कटाव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया।

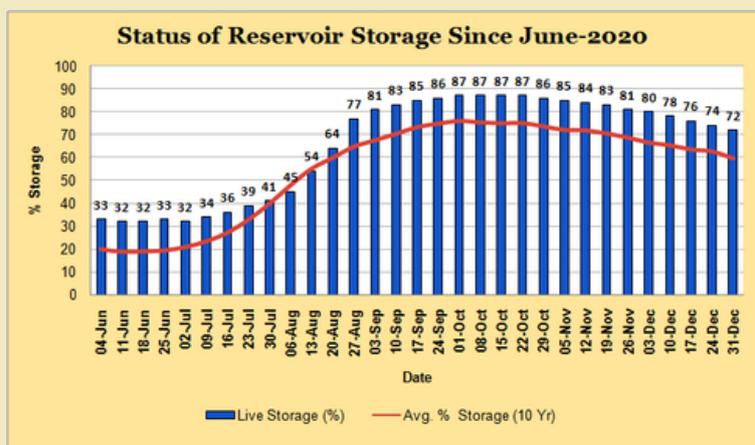
## आंकड़ा



## जलाशय की निगरानी

के.ज.आ. नियमित रूप से साप्ताहिक आधार पर देश के 128 जलाशयों के सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी करता है और हर गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी करता है। इन 128 जलाशयों में से, 44 जलाशयों में 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित जलविद्युत क्षमता है। इन 128 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 172.132 अरब घन मीटर है जो देश में निर्मित अनुमानित 257.812 अरब घन मीटर की सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 66.77% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 31.12.2020 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण 123.881 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता का 72% है। हालांकि, पिछले वर्ष इन जलाशयों में इसी अवधि के लिए उपलब्ध सक्रिय भंडारण 135.791 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों के सक्रिय भंडारण का औसत 102.51 बीसीएम था। इस प्रकार, 31.12.2020 के अनुसार बुलेटिन के अनुसार 128 जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सक्रिय भंडारण का 91% है और पिछले दस वर्षों के औसत भंडारण का 121% है।



## तट बांध निर्माण के कारण सिल्टेशन पर बैठक

व्यवहार्य बाढ़ नियंत्रण संरचना के रूप तटबंध की सक्षमता एवम बाढ़ के कारण के संबंध में सदस्य (नदी प्रबन्ध), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक तकनीकी समूह का गठन 02.11.2020 को किया गया। प्रथम तकनीकी बैठक

## प्रशिक्षण

एनडब्ल्यूए, के.ज.आ., पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण

क्रम संख्या	विषय	अवधि	प्रतिभागी
1.	वेबिनार 8: भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद-चुनौतियाँ: -कृष्णा जल विवाद-I-एक अध्ययन <a href="https://youtu.be/hkfvHE2Tw5w">https://youtu.be/hkfvHE2Tw5w</a>	01.12.2020	110 केंद्रीय एवं राज्य अधिकारी
2.	स्कूल शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम - बैच डी	01-03 दिसंबर 2020	158 शिक्षक स्कूल
3.	स्कूल शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम - बैच ई	02-04 दिसंबर 2020	137 शिक्षक स्कूल
4.	वेबिनार 9: भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद-चुनौतियाँ: कृष्णा जल विवाद -II-एक अध्ययन <a href="https://youtu.be/gttmrmjIHm0">https://youtu.be/gttmrmjIHm0</a>	07.12.2020	95 केंद्रीय और राज्य अधिकारी
5.	स्कूल शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम - बैच जी	08-10 दिसंबर, 2020	145 शिक्षक स्कूल
6.	स्कूल शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम - बैच एच	09-11 दिसंबर 2020	107 शिक्षक स्कूल
7.	स्कूल शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम - बैच आई	14-16 दिसंबर 2020	117 शिक्षक स्कूल
8.	वेबिनार 10: भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद-चुनौतियाँ: नर्मदा जल विवाद -एक अध्ययन <a href="https://youtu.be/sFty50vkPCL">https://youtu.be/sFty50vkPCL</a>	14.12.2020	80 केंद्रीय और राज्य अधिकारी
9.	बाढ़ परिसंपत्तियों के जीआईएस आधारित मानचित्रण पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उद्देश्य उन्मुख प्रशिक्षण	14 -18 दिसंबर 2020	के.ज.आ. के 40 अधिकारी
10.	स्कूल शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम - बैच जे	15-17 दिसंबर 2020	120 शिक्षक स्कूल
11.	वेबिनार 11: भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद-चुनौतियाँ: रावी और ब्यास जल विवाद -एक अध्ययन <a href="https://youtu.be/cTuogJEMhIA">https://youtu.be/cTuogJEMhIA</a>	21.12.2020	80 केंद्रीय और राज्य अधिकारी
12.	अंतरिक्ष इनपुट का उपयोग करके भारत में जल की उपलब्धता का पुनरीक्षण पर प्रशिक्षण-सह वेबिनार	22-24 दिसंबर, 2020	राज्य / केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र के 132 प्रतिभागी

01.12.2020 को हुई। तदोपरान्त, इस बैठक का कार्यवृत्त सभी प्रतिभागियों को परिचालित किया गया तथा उनसे इनपुट मांगे गए। सभी प्रतिभागियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर 08.01.2021 को दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी।

## देश में बाढ़ की स्थिति

विभिन्न बेसिनों में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 01.05.2020 को शुरू हुई। 01 मई से 31 दिसम्बर, 2020 के बीच 11721 बाढ़ पूर्वानुमान (8243 लेवल एवं 3478 इनफ्लो) जारी किए गए, जिसमें से 11198 (8132 लेवल एवं 3065 इनफ्लो) पूर्वानुमान 95.53% की प्रतिशत की सटीकता के साथ सटीकता सीमा के भीतर थे। दिसंबर माह में गंभीर बाढ़ स्थिति के लिए 1131 आरेंज बुलेटिन एवं चरम बाढ़ स्थिति के लिए 797 रेड बुलेटिन केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से जारी किए गए।

**01.05.2020 से 31.12.2020 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश**

### चरम बाढ़ की स्थिति

सात बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गयी।

क्र. सं.	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन
1.	असम	शिवसागर	दिखो	शिवसागर
2.		गोपालगंज	गंडक	डुमरीघाट
3.		मुजफ्फरपुर	गंडक	रेवाघाट
4.	बिहार	समस्तीपुर	बुढ़ी गंडक	रोसरा
5.	उड़ीसा	बालासोर	सुवर्णरेखा	भवानीरोड ब्रिज
6.	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	गोदावरी	चिंतुरु
7.	कर्नाटक	गुलबर्ग	भीमा	देवनगांव ब्रिज

41 बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर भी चरम बाढ़ की स्थिति देखी गयी।

### बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों के लिए गंभीर बाढ़ स्थिति

अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, छत्तीसगढ़ और गुजरात में 88 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गयी।

## डीडी न्यूज : आपदा का सामना

मौसम पूर्वानुमान तकनीक में प्रगति, मौसम विज्ञानी आंकड़े तथा और अधिक सटीक मौसम पूर्वानुमान संपूर्ण विश्व में लाखों लोगों को आपदा की स्थिति में लाभ पहुंचा रहे हैं। भारत जैसे देशों में, गांवों तक मौसम चेतावनी तथा भविष्यवाणी पहुंचाना चुनौतीपूर्ण काम है। उल्लेखनीय कार्य किया जा चुका है और अब चेतावनी प्रणाली राज्य, जिला एवं तहसील स्तर तक विकसित किया गया है।

दिनांक 13.12.2020 को मौसम पूर्वानुमान तकनीकी के संबंध में एक पैनल परिचर्चा दूरदर्शन पर प्रसारित की गई, जिसमें निम्नांकित प्रतिभागियों ने भाग लिया:

क्र.सं.	नाम और पदनाम	विभाग/एजेंसी
1.	ले.जे.सैयद अता हसनैन, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम (सेवानिवृत्त), सदस्य	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)
2.	श्री शरद चन्द्र, निदेशक	केंद्रीय जल आयोग
3.	श्री लक्ष्मण सिंह राठौर, पूर्व महानिदेशक	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

## सामान्य से अधिक बाढ़ स्थिति

असम, बिहार उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिसा, तेलंगाना, उत्तराखंड, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल में 34 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर सामान्य से अधिक बाढ़ स्थिति की देखी गयी।

## निर्धारित सीमा से ऊपर अंतर्वाह वाले जलाशय

पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में 88 जलाशयों ने बाढ़ पूर्वानुमान के लिए निर्धारित सीमा से अधिक अंतर्वाह प्राप्त किया।



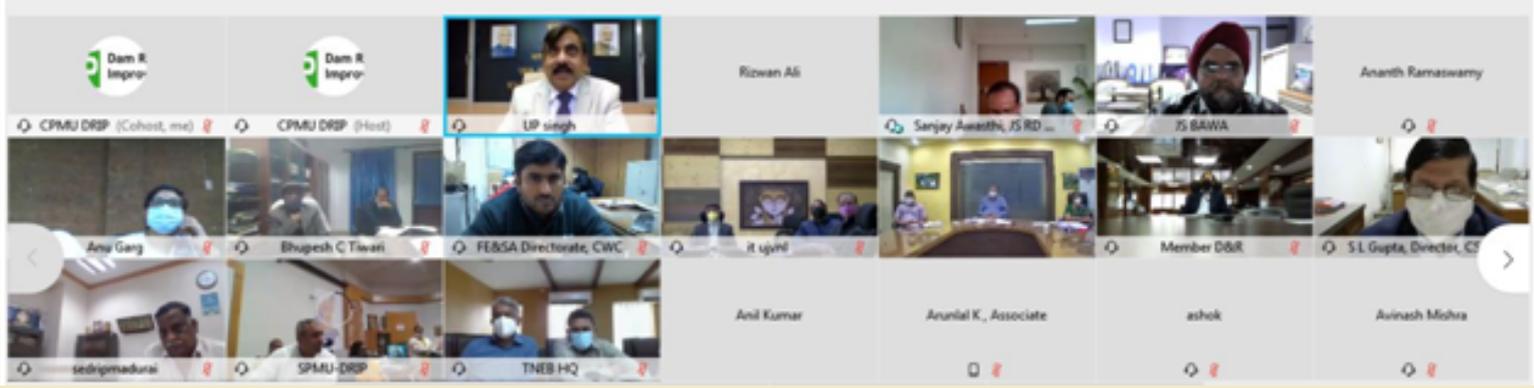
इस पैनल परिचर्चा में भारत सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे एक नई मौसम पूर्वानुमान तथा चेतावनी प्रणाली पर प्रकाश डाला गया। इस नई प्रणाली की निम्नांकित विशेषताएं होंगी :-

1. एकीकृत समान चेतावनी प्रोटोकॉल
2. डाटा आधारित सार्वजनिक चेतावनी एवं सूचना साझेदारी
3. इस नई प्रणाली में चेतावनी देने वाली एजेंसियों को एकीकृत किया जाएगा।
4. इन चेतावनी में राज्य स्तर पर सुधार की जाएगी।
5. सूनामी जैसी आपदाओं के समय अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी देने वाली एजेंसियां बिना प्रतीक्षा किए हुए सीधे चेतावनी जारी कर सकती हैं।



## ड्रिप के तहत गतिविधियां

### ड्रिप के लिए राष्ट्र स्तरीय संचालन समिति की 10वीं बैठक



ड्रिप के लिए राष्ट्र स्तरीय संचालन समिति (एनएलएससी) की अध्यक्षता सचिव, ज.सं. न.वि. एवं गं.सं.वि. द्वारा की जाती है तथा इसमें केंद्रीय जल आयोग, आईएमडी, नीति आयोग तथा अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों का प्रतिनिधित्व है। एनएलएससी को इस परियोजना के निरूपण एवं क्रियान्वयन हेतु नीतिगत दिशानिर्देश देने तथा इसकी प्रगति की समीक्षा करने का अधिदेश प्राप्त है। ड्रिप के लिए एनएलएससी की 10वीं बैठक का आयोजन सचिव, ज.सं. न.वि. एवं गं.सं.वि. की अध्यक्षता में 21.12.2020 को आयोजित की गई। इसमें एनएलएससी के सभी सदस्यों तथा

विशेष आमंत्रितों द्वारा भाग लिया गया। इस समिति को इन परियोजनाओं की प्रगति तथा इनमें आनेवाली बाधा से अवगत कराया गया। ड्रिप पर एक वृत्तचित्र सभी सदस्यों को दिखाया गया। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि सभी सहयोगी एजेंसियां मार्च, 2021 तक प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य को पूरा करें और चालू पुनर्वास गतिविधियों को पूर्ण करें। ड्रिप फेज- दो में ड्रिप पार्टनर एजेंसियों की प्रगति की भी समीक्षा की गई तथा समिति के अध्यक्ष ने डीईए की तैयारी मानदंडों को पूरा करने हेतु निविदा प्रक्रिया को तीव्र करने का निदेश दिया।

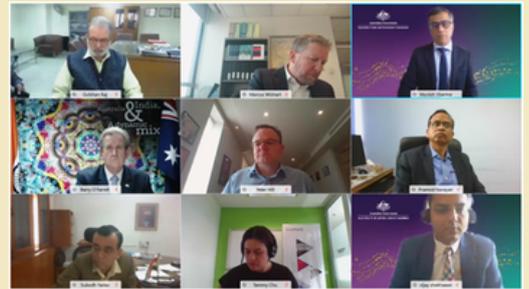
### ड्रिप फेज़ दो के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव मध्य प्रदेश डब्ल्यूआरडी के साथ समीक्षा बैठक

मध्य प्रदेश डब्ल्यूआरडी की तैयारी की समीक्षा तथा डीईए की तैयारी मानदंडों को पूरा करने के लिए सिविल वर्क्स हेतु लंबित निविदाओं की प्रक्रिया को तेज करने के लिए मध्य प्रदेश डब्ल्यूआरडी की बैठक 9.12.2020 को भोपाल में आयोजित की गई। इस बैठक में एमपी डब्ल्यूआर डी प्रतिनिधिमंडल ने श्री एस एन

मिश्रा अतिरिक्त मुख्य सचिव एमपी डब्ल्यूआरडी के नेतृत्व में तथा सीपीएमयू, केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने श्री गुलशन राज, मुख्य अभियंता, डीएसओ तथा परियोजना निदेशक, ड्रिप फेज़-II के नेतृत्व में भाग लिया।

### ऑस्ट्रेलिया-भारत जल वार्ता में जल शक्ति मंत्रालय तथा केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा भागीदारी

ऑस्ट्रेलिया-भारत जल वार्ता ऑस्ट्रेलियाई ट्रेड कौंसुलेट जनरल द्वारा आयोजित किया गया। इस वार्ता का विषय बांध सुरक्षा और प्रचालन प्रबंधन है। श्री सुबोध यादव, संयुक्त सचिव, प्रशासन ने शुरुआती सत्र में उद्घाटन संबोधन किया। श्री गुलशन राज, परियोजना निदेशक, ड्रिप फेज़-II और फेज़-III और श्री प्रमोद नारायण, परियोजना निदेशक, ड्रिप ने पैनल परिचर्चा में भाग लिया। इस आयोजन में सभी ड्रिप पार्टनर एजेंसियों ने भाग लिया।



### कर्नाटक डब्ल्यूआरडी के साथ हितधारी परामर्श बैठक

अलमाटी बांध एवं नारायणपुर बांध के संबंध में प्रकाशित आपातकाल योजना के क्रियान्वयन आवश्यकता के भाग के रूप में प्रचार प्रसार करने हेतु हितधारियों की



परामर्श बैठक 11.12.2020 को आयोजित की गई। केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों सहित सभी हितधारियों ने इस बैठक में भाग लिया। एक प्रभावित जिला नारायण पेठ जिला के लिए तेलंगाना राज्य के कार्मिकों तथा कर्नाटक के चार प्रभावित जिलों विजयपुरा,

बागलकोट, यादगीर तथा रायचूर जिला के कार्मिकों ने इस बैठक में भाग लिया। यह सभी हितधारियों को संबंधित जोखिम के विषय में सूचना देने हेतु जोखिम उपशमन रणनीति का भाग है।

## विद्यमान बांधों की हाइड्रोलिक सुरक्षा के आकलन हेतु मैनुअल मसौदा की समीक्षा के लिए समीक्षा समिति की बैठक

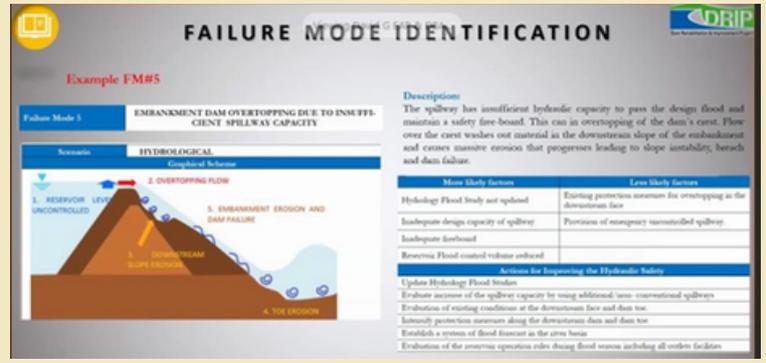
विद्यमान बांधों की हाइड्रोलिक सुरक्षा के आकलन हेतु मैनुअल मसौदा पर समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति ने मसौदा दस्तावेज की सराहना की तथा परियोजना का मार्च 2021 में नियत समापन को ध्यान में रखते हुए इसे अंतिम रूप देने के लिए सहमत हुई। यह मैनुअल चालू ड्रिप में प्रकाशन हेतु नियोजित 14 दिशा निर्देशों में सम्मिलित है।

## ड्रिप फेज़-II के संबंध में एआईआईबी के साथ बैठक

एआईआईबी के साथ दिनांक 29.12.2020 को समीक्षा बैठक की गई जो ड्रिप फेज़ -II के लिए 250 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के ऋण के संबंध में था। ऋण के महत्वपूर्ण शर्तों एवं निबंधनों पर चर्चा की गई। इस योजना से जुड़ने हेतु राज्यों की तैयारी की समीक्षा की गई। इस बैठक में मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, विश्व बैंक तथा एआईआईबी के कार्मिकों ने भाग लिया।

## आईएमसीटी

गृह मंत्रालय द्वारा मानसून ऋतु- 2020, पूर्वोत्तर मानसून तथा चक्रवात निवार के कारण बाढ़/ भूस्खलन से सिंचाई, पेयजल, तटबंध एवं बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं में द्वारा होने वाली क्षति का मौके पर जा कर आकलन हेतु कई अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम गठित की गई हैं। इन आईएमसीटी में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के प्रतिनिधित्व के



लिए केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों को नामित किया गया।

आईएमसीटी की जिला अधिकारियों के साथ बैठक हुई तथा क्षति का आकलन करने हेतु उन्होंने प्रभावित जिलों के दौरे भी किए।

दिसंबर 2020 के दौरान अन्य दौरा का विवरण इस प्रकार है-

क्रम संख्या	राज्य	दौरा की अवधि	जल शक्ति मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी	दौरा किए गए जिले	उद्देश्य
1.	तमिल नाडु	5 से 8 दिसंबर	श्री जे हर्षा, निदेश, केंद्रीय जल आयोग, चेन्नई	चेन्नई दक्षिण चेंगलपट्टु कुड्डालोर, विलुपुरम, चेन्नई उत्तर,तिरुबल्लूर, कांचीपुरम वेल्लोर रानीपेट तिरुपत्तूर।	निवार चक्रवात के दौरान हुई हानि
2.	आंध्र प्रदेश	17 से 19 दिसंबर	श्री पी देवेंद्र राव, निदेशक, केंद्रीय जल आयोग, हैदराबाद	कृष्णा गुंटुर प्रकाशम एसपीआर वेल्लोर,वाईएसआर और चित्तूर	-तदैव-
3.	हिमाचल प्रदेश	30 दिसंबर 2020 से 1 जनवरी 2021	श्री पीयूष रंजन, निदेशक केंद्रीय जल आयोग, शिमला	शिमला,सोलन ऊना,हमीरपुर और बिलासपुर	मानसून ऋतु 2020 के दौरानबाढ़,भूस्खलन, बादल फटना



आंध्र प्रदेश



तमिलनाडु



हिमाचल प्रदेश



हिमाचल प्रदेश

## गिरि मध्यम सिंचाई परियोजना का निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन

गिरि मध्यम सिंचाई परियोजना की शुरुआत वर्ष 1982 में हुई जिसकी लेफ्ट बैंक कैनाल तथा राइट बैंक कैनाल के तहत संयुक्त रूप से अधिकतम सिंचाई क्षमता 5263 हेक्टेयर है। इस परियोजना के लिए सीसीए 3891 हेक्टेयर है। यह परियोजना 1982 में 8.23 करोड़ों रुपए की लागत से पूरी की गई। यह परियोजना तहसील पोंटा साहब जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में बाहरी हिमालय रेंज जिसे शिवालिक कहा जाता है में स्थित है। गिरि मध्यम सिंचाई परियोजना हिमाचल प्रदेश की परियोजना उपरांत मूल्यांकन अध्ययन (पीईएस) एग्री इकोनोमिक रिसर्च सेंटर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला द्वारा किया गया।

पीईएस से निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं।

- दोनों नहरों के क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं में कई जगह आंशिक क्षति पाई गई है। गाद भरने के कारण विपथन तालाब और नहरों की बहाव क्षमता अभिकल्पित मूल्य से कम पाया गया है।
- परियोजना जल उपयोग दक्षता की गणना केंद्रीय जल आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार की गयी और 49.52% पायी गई।

कमांड में भूजल की गहराई 9.5 मीटर (अगस्त) से 24.4 मीटर (जून) तक है। इस अवधि के दौरान राइट बैंक कैनाल की सिंचाई क्षमता का उपयोग 72.8-91% के बीच रही है, जिसका औसत 79.4% रहा है और लेफ्ट बैंक कैनाल के लिए यह 22.2- 30. 4% के बीच रही है, जिसका औसत 26.9% है। इसमें प्रचलनात्मक जोत की साइज 1.48 हेक्टेयर परियोजना की शुरुआत से पहले 1.48 हेक्टेयर से घटकर 0.74 हेक्टेयर हो गई है। सिंचाई की शुरुआत से पहले फसल बोने के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। बेहतर सिंचाई सुविधा के कारण अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई है।

- प्रति घर कुल कृषि आय रुपए 68774 था। इसके अलावा गैर कृषि आय प्रति घर रुपए 148598 है। कृषि रोजगार प्रति घर 626 मानव दिवस प्रतिवर्ष पाया गया है जबकि गैर कृषि रोजगार प्रति घर 413 मानव दिवस है।
- परियोजना से पहले पारिवारिक आकार 8.98 थी जो वर्तमान में 5.69 घटकर हो गई है परंतु साक्षरता का प्रतिशत 38 से बढ़कर 78% हो गया है। परियोजना निरूपण के समय लाभ लागत अनुपात 2.92 था जो अब 2.08 पाया गया है।

## 31.12.2020 तक विभिन्न योजनाओं/अवयव की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/घटक का नाम	संशोधित अनुमान (2020-21)	व्यय	व्यय (प्रतिशत में)
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	130.00	88.345	67.96%
2.	जल संसाधन विकास योजनाओं का अन्वेषण (आईडब्ल्यूआरडी)	9.00	6.332	70.35%
3.	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	10.576	7.327	69.28%
4.	इंफ्रास्ट्रक्चर विकास (आईडी) योजनाएं	5.75	5.025	87.35%
5.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	8.886	4.827	54.32%
6.	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना	30.00	21.64	72.13%

## जल क्षेत्र समाचार

- तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा बांध बनाएगा चीन (पंजाब केसरी, 01.12.2020)
- चीन की पनबिजली परियोजना का जवाब बहुउद्देशीय जलाशय (हरि भूमि, 03.12.2020)
- गोवा में जल—जीवन मिशन सफल छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों को इंतजार (हरि भूमि, 04.12.2020)
- पम्बन के नजदीक 'बुरेवी', तमिलनाडु—पुडुचेरी में भारी बारिश (हरि भूमि, 04.12.2020)
- यूपी—एमपी के बीच अधिकांश बिन्दुओं पर बनी सहमति, जल्द शुरू होगी दो साल से अटकी केन—बेतवा लिंक परियोजना (हरि भूमि, 09.12.2020)
- देश की नदियां भारतीय संस्कृति और पर्यटन का महत्वपूर्ण हिस्सा : केन्द्रीय मंत्री पटेल (हरिभूमि, 13.12.2020)
- नदियों को जोड़ने और बांध निर्माण जैसे लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करे केंद्र सरकार (हरिभूमि, 16.12.2020)
- जल अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग करेगा नार्वे, स्वच्छ गंगा मिशन के थिंक टैंक सी—गंगा के साथ जैव—अर्थव्यवस्था शोध संस्थान ने किया (हरिभूमि, 16.12.2020)

- एसवाईएल नहर के मुद्दे पर किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी (हरिभूमि, 17.12.2020)
- जल प्रभाव सम्मेलन के अंतिम दिन 'नदी संरक्षण समन्वित नौपरिवहन और बाढ़ के प्रबंधन' पर विशेषज्ञों ने किया मंथन (हरिभूमि, 17.12.2020)
- जल जीवन मिशन में अब तक 278 लाख परिवारों को मुहैया कराए नल जल कनेक्शन (हरिभूमि, 20.12.2020)
- देश की पहली वाटर टनल तैयार, यह 8.7 किमी लंबी (दैनिक भास्कर, 20.12.2020)
- दिल्ली में गंगाजल लाने पर खर्च होंगे दो हजार करोड़ (दैनिक जागरण, 22.12.2020)
- गंगा के किनारों को बनाया जाएगा जैविक खेती का हब (राष्ट्रीय सहारा, 23.12.2020)
- नहाने के लायक भी नहीं यमुना का पानी : रिपोर्ट (नवभारत टाइम्स, 31.12.2020)
- बिहार के जल निकायों के मानचित्र का एटलस बनेगा (हिन्दुस्तान, 31.12.2020)

## उत्तर कोयल के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की 29वीं बैठक

उत्तरी कोयल परियोजना (एनकेपी) के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की 29वीं बैठक दिनांक 04.12.2020 को सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), के.ज.आ. एवं अध्यक्ष (टीईसी) की अध्यक्षता में केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित की गई थी। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) और क्षेत्रीय कार्यालयों, सीएसएमआरएस, बिहार एवं झारखंड राज्य सरकारों एवं वाफ्कोस के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

बैठक के दौरान, वाफ्कोस ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों के लिए शिविर / पिकेट के निर्माण के लिए कार्य पहले ही दिए जा चुके हैं। बिहार सरकार के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि वे बिहार के भाग में आरएमसी के पूर्ण अस्तर के मुद्दे पर शीघ्रतिशीघ्र अपने विचार व्यक्त करें ताकि बिना किसी और देरी के बिहार के हिस्से में



आरएमसी के कार्यों को भी 7वें आरसीई के अनुसार बढ़े हुए लागत के अनुमोदन के साथ लिया जा सके। अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा मदों जैसे भूमि अधिग्रहण की स्थिति, वाफ्कोस द्वारा परियोजना के शेष कार्यों के विभिन्न घटकों की प्रगति, राइट मैन कैनाल (आरएमसी) में नहर लाइनिंग में एलडीपीई शीट की मोटाई का मुद्दा, परियोजना की बाई मुख्य नहर की कंडी वितरण प्रणाली का डिजाइन और रेखाचित्र आदि मुख्य विषयों पर चर्चा हुई।

## गैलरी



तत्कालीन अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग ने के.ज.आ. के अधिकारियों के साथ दिनांक 28.12.2020 को हथनीकुंड बैराज, प्रस्तावित आदि बद्दी बांध और बैराज परियोजना स्थल का दौरा किया



पीएमएसकेवाई-एआईबीपी के तहत प्राथमिकता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु आयुक्त (एसपीआर) जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 18.12.2020 को आयोजित बैठक में श्री योकी विजय, निदेशक (प्रबोधन) / अधीक्षण अभियंता (समन्वय), के.ज.आ., गांधीनगर, श्री अमिताभ मीना, उपनिदेशक (प्रबोधन), गांधीनगर ने भाग लिया।



दिनांक 22.12.2020 को के.ज.आ. (मुख्यालय) के जीएसआई डिजाइनरों द्वारा हौरा और चंपई चेर्रा बांध परियोजना, त्रिपुरा का संयुक्त दौरा



सदस्य (नदी प्रबंध), के.ज.आ. द्वारा 4-5 दिसंबर 2020 के दौरान प्रेक्षण स्थल (सिकंदरपुर, समस्तीपुर और रोसरा) निरीक्षण



के.ज.आ. द्वारा जम्मू और कश्मीर के दूरस्थ क्षेत्रों में बेरिनियम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए ड्रॉन द्वारा स्थलाकृतिक सर्वेक्षण कार्य के चित्र। परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ की पंढार घाटी में चिनाब नदी पर प्रस्तावित है।



मुख्य अभियंता, महानदी और पूर्वी नदियों संगठन (एमएंडईआरओ) की उपस्थिति में राजघाट में नए एडीसीपी का निरीक्षण और परीक्षण

## ब्रह्मपुत्र बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति की 11वीं बैठक

"ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप की सुरक्षा" योजना के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति की 11वीं बैठक / दौरा कार्यक्रम दिनांक 29-30 दिसंबर, 2020 के

### सेवा निवृत्ति

श्री, राजेंद्र कुमार जैन अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग और श्री साई सुंदरम, निदेशक दिनांक 31.12.2020 को अपनी 35 वर्षों की सरकारी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों ने उन्हें विदाई दी और सेवानिवृत्त

### पदोन्नति

श्री एस के हालदार, एक नियमित उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) और श्री कुशविंदर वोहरा, केंद्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह 'ए') सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) अधिकारी क्रमशः अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग और उच्चतर ग्रेड (एचएजी) के पद पर पदोन्नत किए गए। श्री कुशविंदर वोहरा को सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), के.ज.आ. के रूप में तैनात किया गया।

दौरान केंद्रीय जल आयोग के सदस्य (नदी प्रबंध) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें माजुली द्वीप के संरक्षण के लिए चल रहे कार्यों के बारे में सुझाव दिए गए।

अधिकारियों के साथ उनके कार्यकाल के अनुभव को याद किया। श्री यू.पी.सिंह, सचिव, जल शक्ति मंत्रालय और अन्य सेवा निवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।



श्री एस.के. हालदार,  
अध्यक्ष, के.ज.आ.



श्री कुशविंदर वोहरा,  
सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी),  
के.ज.आ.

## सैलिनिटी इंग्रेस मैनेजमेंट परियोजनाओं के लिए तीसरी बैठक

सैलिनिटी इंग्रेस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डीपीआर तथा नई स्कीम की तैयारी और डेल्टा क्षेत्रों में सैलिनिटी इंग्रेस के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समिति की तीसरी बैठक दिनांक 09.12.2020 को श्री रीडिंग शिमरे, मुख्य अभियंता (पीएंडडी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी। बैठक में के.ज.आ., एनआईएच, सीडब्ल्यूपीआरएस और सीजीडब्ल्यूबी के सदस्यों ने भाग लिया। "बैठक के दौरान तटीय क्षेत्रों में सैलिनिटी इंग्रेस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए दिशानिर्देश" को अंतिम रूप दिया गया।

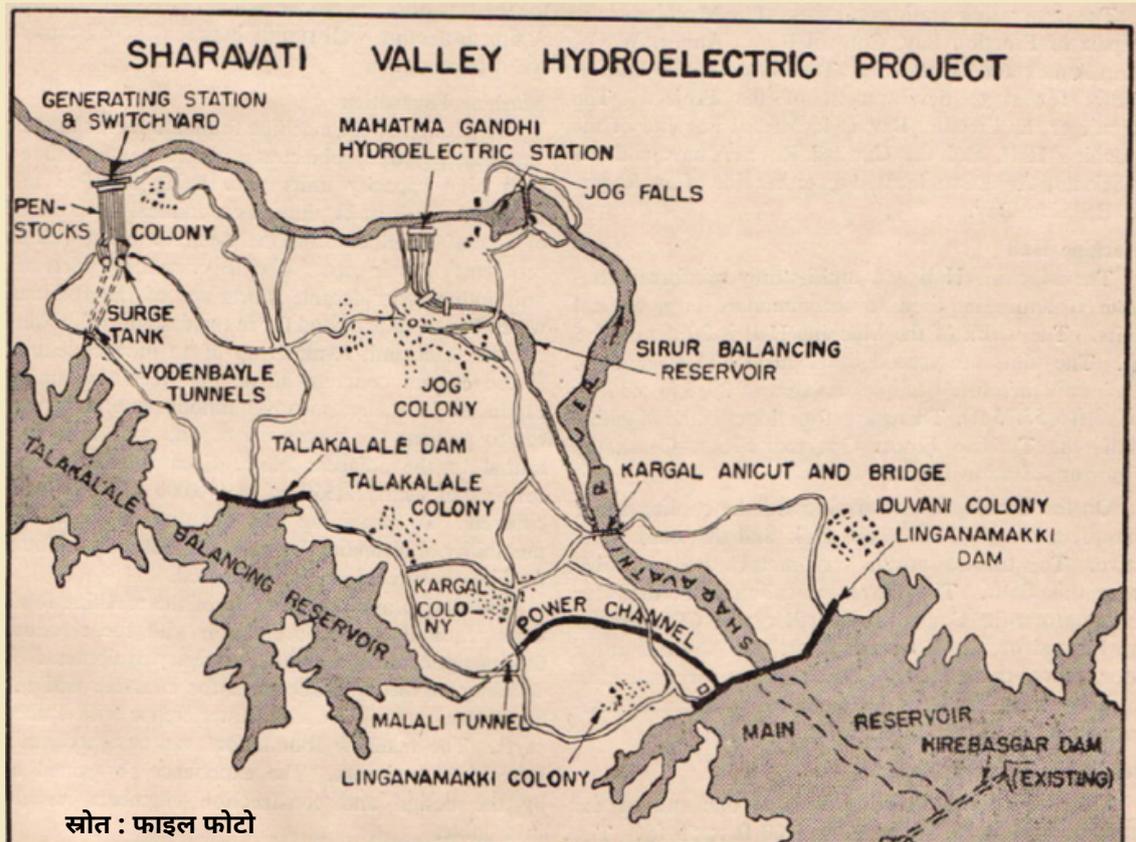


## इतिहास-शरवती हाइड्रो पावर प्लांट

कर्नाटक राज्य के शरवती हाइड्रो पावर प्लांट देश के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों में से एक है, जिसमें एक ही स्थान पर 1035 मेगावाट संस्थापित क्षमता है।

### इतिहास

शिमोगा जिले में अंबुतीर्थ के पास 730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, शरवती नदी उत्तर-पश्चिम दिशा में बहती है। 132 किलोमीटर की अपनी लंबी यात्रा में, शरवती नदी कई सहायक नदियों से जुड़ती है। अपनी जलमार्ग की यात्रा में 80 किमी की दूरी पर नदी 293 मीटर ऊंचे पहाड़ से नीचे की ओर गिरती है और एक अति रमणीय चमत्कार जिसे जोग जल-प्रपात जाना जाता है, बनाती है। इस लुभावने जल-प्रपात से होकर नदी के पास अरब सागर में मिलने



स्रोत : फाइल फोटो

तक अपनी यात्रा जारी रखती है। शरवती से बिजली विकास के प्रस्ताव लगभग उसी समय बनाए गए थे, जब शिवसमुद्रम, जो भारत की पहली हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना के रूप में प्रसिद्ध है, के लिए प्रस्ताव बनाए थे। श्री एम विश्वेश्वरैया द्वारा इस प्रस्ताव को 1920 में फिर से संशोधित किया गया था और इसके लिए अन्वेषण भी किए गए थे। लेकिन 1948 के आसपास पहली बार शरवती नदी पर जोग जलप्रपात (गेरुसोप्पा) के पास महात्मा गांधी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की शुरुवात हुई। यह 48 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ खुला और बाद में इसे 120 मेगावाट में अपग्रेड किया गया। हालाँकि, उपलब्ध पावर क्षमता को देखते हुए, तीन चरणों में एक एकीकृत शरवती घाटी परियोजना की योजना बनाई गई। एकीकृत परियोजना में विभिन्न घटक शामिल थे:

- लिंगनामक्की बांध / जलाशय (4.420 बीसीएम)
- एक बैलेंसिंग जलाशय (0.140 बीसीएम) बनाने के सहायक नदी पर तलाकाले बांध जिसका नाम नदी के नाम पर रखा गया।
- जल संवाहक प्रणाली
- पावर हाउस (10x89.1 मेगावाट) - 2 यूनिट्स-चरण-1, 6 यूनिट्स-चरण-2, 2 यूनिट्स-चरण-3

श्री एस.के. पाटिल, केंद्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री, ने दिनांक 05.02.1958 को जोग प्रपात से पांच मील की दूरी पर मैसूर के लिंगनामक्की में शरवती जलविद्युत परियोजना के निर्माण का उदघाटन किया। परियोजना के महत्व को देखते हुए, इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी शामिल किया गया था। इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका से 48.7 करोड़ रुपये (102 मिलियन अमेरिकी डालर) की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। माननीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिनांक 24.01.1965 को 89.1 मेगा वाट वाले पहली इकाई चालू किया गया था।

### सीडब्ल्यूपीसी की भूमिका

इस परियोजना को राज्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया गया था। हालांकि, योजना की जल विज्ञानीय परीक्षा में केंद्रीय जल और विद्युत आयोग (सीडब्ल्यूपीसी) शामिल था। उनके अवलोकन के आधार पर, योजना की पावर क्षमता को संशोधित कर 891 मेगावाट कर दिया गया। सीडब्ल्यूपीसी ने कार्यों के कई घटकों हेतु अभिकल्प के अंतिम रूप देने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की।

### नए सुधार, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजना

प्रत्येक उत्पादन इकाई का नवीकरण करके 89.1 मेगावाट से 103.5 मेगावाट तक के अपग्रेडेशन किया गया है। शरवती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आज कर्नाटक के बिजली उत्पादन की प्रमुख रीढ़ है।

माननीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री 24.01.1965 को 89.1 मेगावाट की पहली इकाई चालू करते हुए



शरवती परियोजना की अनूठी विशेषता एक स्थान पर 1035 मेगावाट संसाधन की स्थापना है, जिसकी वार्षिक उत्पादन लगभग 5000 मिलियन यूनिट है। पावर स्टेशन में उपयोग की जाने वाली टर्बाइनों की कुल संख्या 10 है और प्रति टर्बाइन की क्षमता 103.5 मेगावाट है।

- टरबाइन का प्रकार: वरटिकल पेल्टन
- डिजाइन हेड: 443.18 मीटर
- डिजाइन निस्सरण: 28.5 क्यूमेक्स

शरवती पर पहली जलविद्युत परियोजना (एचईपी) अर्थात् महात्मा गांधी एचईपी की वर्तमान स्थापित क्षमता 139.20 मे.वा.है। इसके अलावा, अम्बुतीर्थ पावर प्राइवेट लिमिटेड (एपीपीएल) ने उपरोक्त परियोजना की टेल रेस के पानी का उपयोग करते हुए 22 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली बिजली परियोजना विकसित की है।

उपरोक्त के अलावा, 2 इकाइयों वाले लिंगनामक्की बांध बिजलीघर की स्थापित क्षमता 55 मेगावाट है। शरवती नदी की क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए, कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (KPCL) ने 60 मेगावाट की चार जेनरेटिंग यूनिट्स स्थापित कर गेरुसोपा बांध परियोजना को कुल स्थापित क्षमता 240 मेगावाट तक बढ़ायी है। आज, स्थापित क्षमता लगभग 1500 मेगावाट है, जो इस तथ्य को देखते हुए काफी उल्लेखनीय है कि नदी की लंबाई मात्र 132 किमी है। केपीसीएल ने निचले गेरुसोप्पा जलाशय से ऊपरी तलाकाले जलाशय में जल पंप करके 2000 मेगावाट वाली पंप स्टोरेज पनबिजली योजना की परिकल्पना की है।

जोग जलप्रपात भारत के पर्यटन मानचित्र पर विश्व प्रसिद्ध है। बांधों, जलाशय, चैनलों और सुरंगों ने जोग के आकर्षण को और बढ़ा दिया है।



### केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,  
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध  
कार्यालय

### संपादक मंडल

- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ) - सदस्य
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री दीपक कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री भूपिन्द्र सिंह, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी-सी) - सदस्य
- श्री के.वी. प्रसाद, निदेशक(जल प्रणाली अभि.) - सदस्य
- श्री अर्जुन कुमार मधोक, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव

### अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय  
केंद्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066  
ई-मेल: media-cwc@gov.in

